सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।

–चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-264 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, गुरूवार 28 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

बीकानेर में अमित शाह की सुरक्षा समीक्षा बैठक

सीमा प्रबंधन को मिलेगा 360ए मजबूती का ढांचा

हैलो सरकार न्यूज

बीकानेर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर एवं फलोदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सीमा प्रबंधन को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए। बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस एकीकृत प्रयास में स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सीमा प्रबंधन को और अधिक comprehensive एवं मजबूत बनाया जा सके। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध

निर्माणों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का निर्देश दिया।

अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार की मशीनरी के साथ समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया, ताकि घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रैक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें।

गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि साइबर अपराधों के त्वरित निवारण के लिए '1930' कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग किया जाए तथा क्षेत्र में कानून प्रवर्तन व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

बैठक के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया, जिसके माध्यम से अंतिम छोर तक शासन को सुदृढ़ करना, आर्थिक अपराधों को रोकना, बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करना तथा सीमावर्ती जनसंख्या को समर्थन देना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का 100त्न सैचुरेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव-पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें आग्रह किया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यदि राज्य सरकार या अन्य कोई पक्ष अपील करता है, तो उनका पक्ष सुने बिना अदालत कोई भी एकतरफा आदेश पारित न करे।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आगामी 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 14 नवम्बर 2025 को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवंदा की जनहित याचिका को निस्तारित करते समय 15 अप्रेल तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की गई थी।

दरअसल, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन और प्रशासनिक चुनौतियों का हवाला देते हुए कोर्ट से चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसके चलते प्रक्रियाओं में समय लगेगा।

इसी वजह से माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।

सरकार की मंशा वन स्टेट-वन इलेक्शन

सरकार की ओर से कहा गया था सितंबर से दिसंबर के बीच में कई पंचायत के बीच में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा। इससे वन स्टेट-वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा।

आयोग की माफी

इस पूरे मामले में संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली थी। आयोग ने कहा था कि वह चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन राज्य सरकार ने समय पर परिसीमन संबंधी आंकड़े, आरक्षण का डेटा और जरूरी प्रशासनिक जानकारियां उपलब्ध नहीं कराईं। इसी वजह से आयोग समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका।

डेढ़ गुना बढ़े निकाय

इस बार राज्य के 309 निकायों में 10175 वार्डों में चुनाव होंगे। वर्ष 2019 में प्रदेश में 196 नगरीय निकाय थे, जिनमें 7475 वार्ड शामिल थे। परिसीमन और पुनर्गठन के बाद अब 2700 नए वार्ड बनाए गए हैं। अब न्यूनतम 20 वार्ड व अधिकतम 150 वार्ड रखे गए हैं।

जयपुर-सीकर हाईवे पर भीषण हादसा

खाटूश्यामजी जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, 9 लोग घायल

जयपुर। जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) पर बुधवार सुबह खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। तेज रफ्तार टेम्पो क्रूजर ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे होटल में जा घुसी, जिससे तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। इस दौरान होटल के बाहर खड़ी एक अन्य कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

यह दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 7 बजे चौमूं क्षेत्र में स्टेडियम के पास ब्यावरिया कट और हाड़ौता पुलिया क्षेत्र के आसपास हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया।

महाराष्ट्र के श्रद्धालु थे सवार

पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के श्रद्धालु टेम्पो क्रूजर वाहन में सवार होकर खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन के लिए सीकर की ओर जा रहे थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आगे चल रहा ट्रक अचानक मुड़ा या कट लेने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार टेम्पो क्रूजर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह हाईवे किनारे बने होटल में जा घुसा।

तीन लोगों की हुई मौत

हादसे में शालू बाई (75), मेघा (40) और आदेश (18) की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों महाराष्ट्र के परभणी जिले के गंगाखेड़ क्षेत्र के हरंगुल गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो महिलाएं और एक युवक शामिल हैं। शवों को चौमूं के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

9 लोग हुए घायल

हादसे में गीता देवधर, गायत्री देवधर, खुशी जावड़े, अंकिता, रितेश, ऋषिकेश, शकुंतला, सुनीता और यशोदा घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस कार्रवाई में जुटी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन महाराष्ट्र नंबर का था। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात बहाल कराया। मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

राजस्थान में हर मरीज पर नजर, एंटी मलेरिया मिशन शुरू, जून में चलेगा विशेष अभियान

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन-जागरूकता, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के लिए जून माह को 'एंटी मलेरिया माह' के रूप में मनाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान के तहत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर जागरूकता, सर्विलांस और रोकथाम गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और राजस्थान इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जून माह में चलने वाला यह विशेष अभियान आमजन को मच्छरजनित रोगों के प्रति जागरूक बनाने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग्राम स्तर तक चलेंगी जागरूकता और सर्विलांस गतिविधियां

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र के निर्देशानुसार जून 2026 को 'एंटी मलेरिया माह' के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि सघन मॉनिटरिंग, समय पर जांच और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर तक रैलियां, विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रचार अभियान और जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक बुखार पीड़ित व्यक्ति की ब्लड स्लाइड और आरडीटी जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने, साफ-सफाई बनाए रखने और विभिन्न विभागों के समन्वय से रोकथाम गतिविधियां संचालित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों, परियोजना क्षेत्रों तथा शहरी एवं पेरी-अरबन इलाकों में विशेष सर्विलांस अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठकों में आशा सहयोगिनी, एएनएम, सीएचओ, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले अशोक गहलोत, कहा- 'आधा हिस्सा जनता को वापस करो'

हैलो सरकार न्यूजद्व, जयपुर। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के दामों में लगातार वृद्धि से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस लाभ का कम से कम आधा हिस्सा जनता को वापस देना चाहिए, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना लाभ केंद्र सरकार को मिलता है, उसी अनुपात में राज्यों के वैट संग्रह में भी बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं हो रही।

गहलोत ने ईंधन का दाम कम करने का बताया तरीका

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार अतिरिक्त आय का आधा हिस्सा भी जनता को लौटाए, तो पेट्रोल-डीजल के दामों में कुछ कमी लाई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक स्थिति बताने के बजाय अलग तस्वीर पेश कर रही है।

जनता को विश्वास में लेना जरूरी- गहलोत

अंतरराष्ट्रीय हालातों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि यदि दुनिया में युद्ध या अन्य वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन कीमतों पर असर पड़ रहा है, तो सरकार को देश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास में लेना जरूरी है।

विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप

इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी उल्लेख किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को आगाह करते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर कोविड काल तक उन्होंने समय-समय पर अपनी राय रखी और कई मामलों में पहले ही चेतावनी दी थी। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

पेट्रोलियम डीलर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी

दूसरी ओर, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और तेल कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से प्रदेशभर के पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।

राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई

103 नोजल सीज, 110 पंपों पर अनियमितताएं

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। प्रदेश में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की सही मात्रा उपलब्ध कराने तथा पेट्रोल पंपों पर माप एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने 13 मई से 18 मई तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 226 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 110 पेट्रोल पंपों पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई, जबकि 103 नोजल सीज किए गए।

विभाग के अनुसार निरीक्षण अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप संचालकों को नियमित जांच और मशीनों के सही रखरखाव के प्रति जागरूक करना भी था। जांच में अधिकांश पेट्रोल पंप निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए और उपभोक्ताओं को सही मात्रा में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति करते मिले। हालांकि कुछ स्थानों पर वितरण में मामूली अंतर पाया गया, जो तकनीकी कारणों, तापमान, मशीनों की संवेदनशीलता और कैलिब्रेशन की स्थिति से जुड़ा हो सकता है।

60 मामलों में शॉर्ट डिलीवरी, कई पंपों पर दस्तावेजों की कमी

निरीक्षण के दौरान कुल 60 मामले शॉर्ट डिलीवरी यानी निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल या डीजल देने से संबंधित पाए गए। विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित नोजल सीज किए और नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में 40 मिलीलीटर से लेकर 120 मिलीलीटर तक की कमी दर्ज की गई।

इसके अलावा 56 पेट्रोल पंपों पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करने की अनियमितता सामने आई। वहीं 16 मामलों में अप्रमाणित माप उपकरणों का उपयोग पाया गया। विभाग ने इन सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संचालकों को निर्देश दिए कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें।

उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील

विधिक माप विज्ञान विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन 5 लीटर माप के जरिए मशीनों की जांच सुनिश्चित करें और समय-समय पर डिस्पेंसिंग यूनिट्स का कैलिब्रेशन एवं रखरखाव कराते रहें। विभाग का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

विभाग ने आम उपभोक्ताओं से भी जागरूक रहने की अपील की है। यदि किसी पेट्रोल पंप पर कम मात्रा में ईंधन दिए जाने की आशंका हो तो उपभोक्ता मौके पर उपलब्ध 5 लीटर माप से जांच की मांग कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के विशेष निरीक्षण अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि पारदर्शी व्यापार व्यवस्था और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

30 दिन में RWA को कॉमन एरिया और मेंटेनेंस फंड सौंपने का आदेश

ज्वेल्स ऑफ इंडिया में बिल्डर की मनमानी-

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (ऋछ्व-ऋश्वक्र) ने जयपुर के सबसे पॉश और चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक %ज्वेल ऑफ इंडिया% के निवासियों को बड़ी कानूनी जीत दिलाई है। अथॉरिटी ने प्रमोटर की तानाशाही और कब्जा जमाए रखने की प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉमन एरिया और सुख-सुविधाओं पर पहला हक वहां के आवंटियों का है।

रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने %मैसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड% को आदेश दिया है कि वह अगले 30 दिनों के भीतर %ज्वेल ऑफ इंडिया% (फेज-1 और फेज-2) के कॉमन एरिया का संपूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण आधिकारिक रूप से %रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन% (ऋछ्व) के सुपुर्द करे। यह मामला %ज्वेल ऑफ इंडिया-द्ध रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन% द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है।

आरडब्ल्यूए का आरोप था कि प्रोजेक्ट के पूरी तरह विकसित होने और निवासियों के रहने आने के

बावजूद प्रमोटर और उसकी चहेती मेंटेनेंस एजेंसी कॉमन एरिया पर अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। रेरा एक्ट की धारा 11(4) और 17 के तहत यह प्रमोटर का वैधानिक दायित्व है कि वह एक निश्चित समय-सीमा में रखरखाव और कॉमन सुविधाओं का नियंत्रण पंजीकृत आरडब्ल्यूए को हस्तांतरित करे। इसके अलावा, बिल्डर द्वारा आवंटियों से मेंटेनेंस के नाम पर वसूले गए करोड़ों रुपये के %इंटररेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी% (द्ब स्नरूस्) फंड का हस्तांतरण भी अटका हुआ था, जिसे लेकर खरीदारों में भारी आक्रोश था।

अथॉरिटी ने मामले की गंभीरता और 24 नवंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते (रूश्व) का संज्ञान लेते हुए बिल्डर के खिलाफ कड़े विधिक निर्देश जारी किए हैं। अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि प्रमोटर 30 दिनों के भीतर फेज-1 और फेज-2 के सभी कॉमन एरिया, पार्क, क्लब हाउस और अन्य सुविधाओं का परिचालन और परिचालन नियंत्रण आरडब्ल्यूए को सौंपें। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्वीकृत नक्शे, सरकारी स्वीकृतियां, भवन अनुमतियां, विभिन्न एनओसी (ह्रष्टह्य), ऑपरेशनल मैनुअल और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आरडब्ल्यूए को हैंडओवर करने होंगे।

बिल्डर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आवंटियों से अब तक एकत्र किए गए, रोके गए और खर्च किए गए आईएफएमएस (द्बस्नरूस्) फंड का पूरा बैंक स्टेटमेंट और अर्जित ब्याज सहित विस्तृत वित्तीय विवरण 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे। रेरा का यह फैसला उन बड़े प्रमोटरों के लिए एक कड़ा सबक है जो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी मेंटेनेंस फीस वसूलने के लालच में कॉमन एरिया पर कब्जा जमाए रखते हैं। अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि कानून की नजर में पारदर्शिता और आवंटियों का सामूहिक अधिकार सर्वोपरि है, और इसमें किसी भी प्रकार की देरी विधिक कार्यवाही को आमंत्रित करेगी।

जयपुर में सुरक्षित आदर्श कॉरिडोर विकास हेतु क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

जयपुर। गत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा दिए गए निर्देषों की पालना में जयपुर में अजमेरी गेट से सीतापुरा तक सेफ आदर्श कॉरिडोर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत सुरक्षित सड़क डिजाइन, पैदल यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन एवं जंक्शन सुधार कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर दक्षिण) जयपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना से जुड़े इंजीनियरिंग दल की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला कलक्ट्रेट कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

सीएम भजनलाल की प्रदेशवासियों से अपील-भीषण गर्मी में बरतें सावधानी, दिशा-निर्देशों का करें पालन

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजस्थान में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से गर्मी के इस कठिन दौर में विशेष सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी लोग अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ लेने, धूप में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने तथा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों की पालना करने को कहा।

लोगों से सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति सेवा, संवेदनशीलता और परोपकार की भावना पर आधारित रही है। ऐसे समय में लोगों को आगे आकर सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ, छांव और शीतल जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कर मानवीय संवेदनाओं का परिचय देना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासियों की सजगता और सहयोग से इस भीषण गर्मी का सुरक्षित तरीके से सामना किया जा सकता है।

मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट

इधर, मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर नई चेतावनी भी जारी की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में तेज आंधी, हल्की बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बच्चों-बुजुर्गों को अधिक निगरानी की जरूरत

मौसम विभाग के अनुसार हीटवेव का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों पर पड़ सकता है। लंबे समय तक धूप में रहने वाले या शारीरिक श्रम करने वाले लोगों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। किसानों को फसलों और पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय करने की सलाह दी गई है।

आंधी के दौरान सावधान रहने की अपील

विभाग ने आंधी और तेज हवाओं के दौरान लोगों को घरों के भीतर रहने, खिड़की-दरवाजे बंद रखने और बिजली के खंभों, ढीले तारों तथा बड़े पेड़ों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। साथ ही धूलभरी हवाओं से बचने के लिए मास्क या कपड़े से चेहरा ढकने और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगाने की भी सलाह दी गई है।

पर्यावरण चिंतन- बढ़ती गर्मी नहीं, ये है भविष्य की भयावह चेतावनी

लेखक- योगेश कुमार गोयल

- आग उगलता आसमान और हीट वेव की गिरफ्त में भारत

बदलती जलवायु के कारण भारत सहित दुनिया के अनेक हिस्से भीषण हीट वेव की चपेट में है। अब यह संकट पारंपरिक क्षेत्रों से निकलकर तटीय इलाकों तक फैल चुका है। अंधाधुंध शहरीकरण, घटती हरियाली और कंक्रीट के बढ़ते निर्माण से 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे दिन और रातें अत्यधिक गर्म हो रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर दिल्ली की गलियों और विदर्भ के मैदानों तक पारा 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है। यह केवल बढ़ते तापमान का आंकड़ा नहीं है बल्कि यह एक गहराता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक चेतावनी है। हीट वेव अब केवल मौसमी असुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। बढ़ते तापमान, घटती हरियाली और कंक्रीट के फैलते जंगलों ने जीवन को लू की लपटों में समेट दिया है।

मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की है। पिछले चार दशकों में हीट वेव (लू) से होने वाली मौतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि हीट वेव अब केवल अपने पारंपरिक गढ़ (उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत) तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने दक्षिण भारत के उन तटीय इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जो ऐतिहासिक रूप से कम ताप प्रभावित रहते थे। अध्ययन बताते हैं कि 1981 से 2000 के बीच लू की औसत अवधि जहां 2.5 से 5.5 दिन थी, वहीं 2001 से 2020 के बीच यह बढ़कर 8.5 दिन तक पहुंच गई। लू का भौगोलिक दायरा भी 11.9 लाख वर्ग किलोमीटर से फैलकर 18.1 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। यह विस्तार बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की कड़वी हकीकत है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके हैं, जो दिनभर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे मुक्त करते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव पैदा होता है। इस तपती आग में सबसे अधिक जोखिम उन लोगों (रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर) का है, जो खुले आसमान के नीचे अपना वजूद तलाशते हैं। इनके पास न तो कूलिंग सेंटर की सुविधा है और न ही काम के घंटों में लचीलापन। इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग इस बढ़ते 'डिस्कंफर्ट इंडेक्स' के सबसे आसान शिकार बन रहे हैं।

> वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि से आगामी वर्षों में हीट वेव, गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहने और सर्दी के मौसम का समय घटने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इस बारे में वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में अब तक हम केवल पढ़ते-सुनते रहे थे, वह अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत में मई का महीना गर्म हवाओं (लू) का चरम समय होता है और लू की घटनाओं को भी मौसम में दिन-प्रतिदिन बदलाव का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है लेकिन चिंता की बात यही है कि लू की तीव्रता लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि से आगामी वर्षों में हीट वेव, गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहने और सर्दी के मौसम का समय घटने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इस बारे में वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में अब तक हम केवल पढ़ते-सुनते रहे थे, वह अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत में मई का महीना गर्म हवाओं (लू) का चरम समय होता है और लू की घटनाओं को भी मौसम में दिन-प्रतिदिन बदलाव का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है लेकिन चिंता की बात यही है कि लू की तीव्रता लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पिछले करीब डेढ़ दशकों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में रिकॉर्ड किए गए पांच सबसे गर्म वर्ष रहे। आईएमडी के मुताबिक 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए।

यह जानना भी जरूरी कि हीट वेव आखिर है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है, जो प्रायः दो या ज्यादा दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी क्षेत्र के सामान्य औसत तापमान से अधिक हो जाता है तो उसे 'हीट वेव' कहा जाता हं। आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है और यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक लू की श्रेणी में कही जाती है। इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। हीट वेव के कारण लोगों के बीमार होने और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है तथा सैंकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 के बीच हीट वेव के कारण 1.66 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा अब वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है।

आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से ब्रेन स्ट्रोक, हृदयाघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हीट वेव बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू का असर हृदय तथा फेफड़े जैसे अंगों पर सर्वाधिक पड़ता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। हीट वेव से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है, जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी इत्यादि समस्याओं से पीड़ित हैं।

आईएमडी के मुताबिक वैसे तो हर साल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान हीट वेव का दौर चलता है लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं, जिससे हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं और मौतों तथा बीमारियों की आशंका भी बढ़ रही है।

प्रश्न यह है कि भारत में हीट वेव को लेकर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? पिछले 30 वर्षों के तापमान तथा गर्म हवाओं का आकलन करते हुए आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि घटती हरियाली, शहरीकरण तथा कंक्रीट से निर्माण के कारण ही अब प्रतिवर्ष हीट वेव में वृद्धि हो रही है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही शहर में कुछ जगहों पर उच्च तापमान दर्ज किया जाता है तो कुछ जगहों पर तापमान कम रहता है। कुछ स्थानीय कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल अधिक हरे-भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है जबकि चारों ओर बसी कालोनियों तथा ऊंची-ऊंची इमारतों वाले इलाकों में तापमान ज्यादा दर्ज होता है। तकनीकी भाषा में इसे 'अर्बन हीट आईलैंड इफैक्ट' कहा जाता है। पेड़-पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण इत्यादि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरन्तर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ते जाने से हरियाली नष्ट हो रही है और शहरों में हरे-भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को भी सीमेंट तथा कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। दुनियाभर में विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिक जलवायु संकट को ही लू के लिए जिम्मेदार मान रहे है, जिनका कहना है कि शहरीकरण तथा जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक लू से अर्थव्यवस्था को चौतरफा नुकसान होता है। डब्ल्यूएमओ का कहना है कि बढ़ते तापमान का अर्थ हीट वेव का बढ़ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ का पिघलना, समुद्र जलस्तर का बढ़ना तथा मौसम की चरम घटनाओं का और ज्यादा विनाशकारी होना है, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास पर पड़ेगा। इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में लगभग सभी साल पिछले तथा इस दशक से ही रहे हैं। ब्रिटिश मौसम कार्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि जलवायु पविर्तन नहीं हो रहा होता तो ऐसा चरम तापमान प्रत्येक 312 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान में हर तीन साल बाद प्रचण्ड लू की आशंका जताते हुए दावा किया कि जलवायु परिवर्तन गर्मी की तीव्रता को जिस तेजी से बढ़ा रहा है, उससे इन क्षेत्रों के लोगों को आने वाले वर्षों में सौ गुना ज्यादा लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं।

बहरहाल, अत्यधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वहीं हीट वेव का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अत्यधिक गर्मी के कारण करीब 101 अरब घंटे खो देता है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है और 3.5 करोड़ लोगों द्वारा एक वर्ष में 8 घंटे कार्य करने वाले लोगों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। आईएलओ की रिपोर्ट में भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को 4.2 ट्रिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया है। भारत के संदर्भ में इम्पीरियल कॉलेज में जलवायु विज्ञान के सीनियर लेक्चरर डॉ. फेडरिक ओटो कहते हैं कि भारत में मौजूदा गर्म हवाओं का एक बड़ा कारण कोयला तथा अन्य जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना है और जब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद नहीं होगा, तब तक भारत तथा अन्य स्थानों पर हीट वेव और भी गर्म व खतरनाक होती जाएगी। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में भी हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को भी बढ़ावा देना होगा।

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलों के जानकार तथा पर्यावरण पर 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के लेखक हैं)

संपादकीय

न्यायसंगत आरक्षण

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार-बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर-जाल में फंसे परिवार- मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है। वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग-अलग होती है। ऐसी अवस्था में, सबसे निचले स्तर के लोग राज्य के संरक्षण पाने के लिये प्राथमिकता के हकदार हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच-समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है। इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा।

शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार गोवंश

(लेखिका-निर्मल रानी)

भाजपा शासित राजस्थान में जैसलमेर में घटी एक अत्यंत संवेदनशील घटना ने देश के गौ भक्त समाज को झकझोर कर रख दिया। यहां के डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक गायों के सड़े-गले शव और हड्डियां खुले में बिखरे हुए मिले पाये गये। इस जगह का दृश्य इतना भयावह व भीषण दुर्गंध पूर्ण था कि स्थानीय लोग और गौ-प्रेमी स्वभाविक रूप से इसे देखकर क्रोधित व विचलित हो गए। बताया जाता है कि इनमें से कई गायों की मौत ज़हरीला कचरा या पॉलीथिन खाने से हुई। जबकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसी गायों के शव भी थे जिन्हें मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार ने इसी डंपिंग यार्ड में लाकर फेंक दिया था। भाजपा शासित राजस्थान में घटी इस दर्दनाक व शर्मनाक घटना ने सरकार व निजी गौ रक्ष संगठनों के गौ-रक्षा के दावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यह केवल किसी की लापरवाही मात्र का नहीं बल्कि मानवता और हिन्दू आस्था दोनों के ही अपमान से जुड़ा मामला है।

गौरतलब है कि पिछले एक दशक से देश में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को गौरक्षा के नाम पर मारा जा चुका है। मुहम्मद अख़लाक़ और पहलू ख़ान जैसे अनेक लोगों की हत्या की ख़बरें देश विदेश के मीडिया में प्रसारित होकर देश की बदनामी का कारण भी बन चुकी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-17 में इन्हीं कथित गौरक्षकों के संदर्भ में यह कह भी चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 70-80 प्रतिशत लोग फ़र्ज़ी हैं, जो रात में ग़ैर-क़ानूनी काम करते हैं और दिन में गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मोदी ने कहा था कि उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो गोरक्षा के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने और उनका डोज़ियर तैयार करने को भी कहा था। उस समय मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं की कड़ी निंदा भी की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गौ भक्ति के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार्य नहीं है किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने का हक़ नहीं है। उन्होंने असली गोरक्षकों को सलाह दी थी कि उन्हें गायों को प्लास्टिक खाने से बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कटने से ज़्यादा गायें प्लास्टिक और कचरा खाने से मरती हैं।

गाय को लेकर बने देश के इसी तनावपूर्ण वातावरण में देश के मुस्लिम समाज ने उच्च स्तर पर कहीं फ़तवों से तो कहीं दिशा निर्देश जारी कर भारत के मुसलमानों को यह हिदायत जारी की है कि वे गाय की हत्या व गोमांस भक्षण यदि कहीं किया जा रहा है तो उससे पूरी तरह बाज़ आयें। यहाँ तक कि देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अनेक प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं और संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की है। इनके अनुसार ऐसा करने से देश में नफ़रत और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, और बहुसंख्यक समाज की आस्था का सम्मान होगा। कई इस्लामी विद्वानों और मौलानाओं का तो स्पष्ट मत है कि इस्लाम में गौ मांस खाने को सख़्ती से मना किया गया है। पैग़ंबर मोहम्मद साहब के कथनों का हवाला देते हुए मौलानाओं द्वारा यह बताया गया है कि गाय के मांस में बीमारी है और उसके दूध में शिफ़ा अर्थात राहत है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, ताकि गाय को लेकर होने वाली सांप्रदायिक राजनीति पर पूर्ण विराम लग सके।

परन्तु हिंदूवादी संगठनों द्वारा गौ हत्या को लेकर केवल मुसलमानों पर निशाना साधने वालों को इसी सिक्के के दूसरे पहलू को समझना भी ज़रूरी है। इस सन्दर्भ में पिछले दिनों हुए असम चुनावों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वह बयान क़ाबिल -ए -ग़ौर है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार लोगों के घर के अंदर गोमांस खाने अर्थात निजी खान-पान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उन्हें इसे खाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर खाने के बजाय अपने घरों के अंदर खाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से या धार्मिक स्थलों के आसपास इसका सेवन क़ानूनन और सामाजिक भावनाओं के ख़िलाफ़ है। सवाल यह है कि जब गोवध होगा तभी तो गोमांस घरों में भी खाया जा सकेगा ? दूसरे यह कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों व जातियों के लोगों द्वारा भी बड़ी संख्या में गौमांस भक्षण किया जाता है तभी वोट बैंक के मद्देनज़र यह बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। इसी तरह अप्रैल 2017 में केरल के मल्लापुरम लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार एन. श्रीप्रकाश ने मतदाताओं से वादा किया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले बीफ़ की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और साफ़-सुथरे बूचड़ख़ाने खुलवाएंगे। जबकि अभी पिछले दिनों बंगाल में सत्ता में आई भाजपा सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में क़ानूनन केवल उसी गोवंश (गाय) का वध नहीं किया जा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। इस कुतर्क के अनुसार क्या 14 वर्ष से ऊपर की गाय गौ माता की श्रेणी से बाहर हो जाती है?

भारत सरकार में संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का 2015 में दिया गया वह बयान पूरे देश को याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और गोमांस खाता हूँ। क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? उनका तर्क था कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत से लोग बीफ़ खाते हैं और किसी के खान-पान की आदतों या जीवनशैली को उन पर थोपा नहीं जा सकता। साथ ही उसी समय उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत विविधताओं का देश है। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। गोरक्षा पर राजनीति करने वाली सरकार किरेन रिजिजू जैसे गौ मांस भक्षक को मंत्री बनाकर किस आधार पर गोरक्षा की बात कर सकती है ? उधर यही भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बांड के ज़रिए भारत की सबसे बड़ी बीफ़ निर्यातक कंपनियों से लगभग प्रत्येक चुनावों में करोड़ों का चंदा वसूलती है। इसी सत्ता संरक्षण की वजह से 2014 के बाद यानी भाजपा के शासनकाल में भारत का कुल बीफ़ निर्यात काफ़ी बढ़ चुका है। परन्तु स्वयंभू गोरक्षकों को गोहत्या को बढ़ावा देने व इसके पक्ष में तर्क देने वालों से कोई शिकायत नहीं है बल्कि आश्चर्य है कि इनकी सारी दुश्मनी व शिकायत केवल मुसलमानों से ही है ? समझा जा सकता है कि गोवंश की सुरक्षा किसी धर्म जाति से जुड़ा विषय नहीं बल्कि वास्तव में गोवंश शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार है।

मूर्तिकार का सपना

एक मूर्तिकार ने एक रात विचित्र स्वप्न देखा। वह किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठा लिया फिर उसे सामने रखा और औजारों के थैले से छेनी-हथौड़ी निकालकर उसे तराशने के लिए जैसे ही पहली चोट की, पत्थर जोर से चिल्ला पड़ा- मुझे मत मारो। दूसरी बार वह रोने लगा। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पसंद का एक अन्य टुकड़ा उठाया और उसे तराशने लगा।

वह टुकड़ा चुपचाप वार सहता गया और देखते ही देखते उसमें से एक एक देवी की मूर्ती उभर आई। मूर्ति वहीं पेड़ के नीचे रख वह आगे चला गया। फिर कुछ समय बाद वह उसी पुराने रास्ते से गुजरा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि उस मूर्ति की पूजा-अर्चना हो रही है, जो उसने बनाई थी। भीड़ लगी है, भजन आरती हो रही है, भक्तों की पंक्तियां लगी हैं। जब उसके दर्शन का समय आया, तो पास आकर उसने देखा कि उसकी बनाई मूर्ति के सामने न जाने क्या-क्या रखा है। जो पत्थर का पहला टुकड़ा उसने, उसके रोने चिल्लाने पर फेंक दिया था वह भी एक ओर पड़ा है और लोग उसके सिर पर नारियल फोड़ -फोड़ कर देवी की मूर्ति पर चढ़ा रहे है। तभी मूर्तिकार की नींद टूट गई। वह सपने के बारे में सोचने लगा।

उसने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं, उनका जीवन बन जाता है। विश्व उनका सत्कार करता है। पर जो डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं वे बाद में जीवन भर कष्ट झेलते हैं, उनका सत्कार कोई नहीं करता।

विचार मंथन

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बढ़ती आशंकाएं

(लेखक - सनत जैन)

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हालिया फैसला चुनाव आयोग के अधिकारों की पुष्टि करता है। इसके साथ ही इस फैसले से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को वैधानिक अधिकारों के दायरे में माना, परंतु सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई उन आशंकाओं और दस्तावेजी आपत्तियों पर फैसला स्पष्ट नहीं है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है, यह विवाद समाप्त होने के बजाय और अधिक गहराने की आशंका पैदा होने लगी है। एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और सही करना बताया गया था। लेकिन व्यवहार में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें वैध दस्तावेज रखने वाले नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी के अधिकार भी चुनाव आयोग ने स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मतदाता शुद्धिकरण के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पोर्टल से बिना बीएलओ, बिना रिटर्निंग अधिकारी की जानकारी के बिना भौतिक सत्यापन के करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग कर दिए गए। जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद थे। उनके माता-पिता के नाम भी 2003 की मतदाता सूची में थे। उन्हें भी विभिन्न तकनीकी कारणों के आधार पर सूची से बाहर कर दिया गया। इससे प्रश्न उठना स्वाभाविक है, वर्षों से मतदान कर रहे नागरिकों की वैधता पर अचानक संदेह कर उनका नाम कैसे मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जन्मस्थली नागरिकता और मतदाता सूची की स्थिरता और विश्वसनीयता का आधार क्या रहेगा? स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात सामने आ रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग एक करोड नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 28 लाख लोगों ने दस्तावेजों के साथ ट्रिब्यूनल में अपील कर रखी है। यह केवल चुनाव आयोग के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला भी है। इतनी बड़ी संख्या मतदाता सूची से नाम काटना प्रशासनिक त्रुटि का संकेत नहीं है। बल्कि यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े नागरिकों के अधिकार का प्रश्न है। एसआईआर की प्रक्रिया में यदि करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट नहीं है। विधि विशेषज्ञों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अभी तक जो सरकारी सुविधा मिल रही थी, वह बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें जो मुसलमान मतदाता थे, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बताकर उनके लिए अलग से डिटेंशन सेंटर बनाकर रखने की बात की जा रही है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है जो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग को लेकर कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कानून की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एसआईआर के जो नियम ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने तैयार किये, हर राज्य में अलग-अलग तरह के नियम बनाए गए। इसको लेकर यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई महीने तक प्रक्रिया को लेकर सुनवाई की, लेकिन इस संबंध में कोई भी स्पष्टता वाला आदेश नहीं आया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटता है। उसके बाद उसे धार्मिक आधार पर संदेह की दृष्टि से भेदभाव किया जाता है, तो यह केवल चुनावी प्रक्रिया का विषय नहीं रह जाता। सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न बन जाता है।

लोकतंत्र केवल मतदान कराने की व्यवस्था नहीं है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र के विश्वास पर टिका है। जब करोड़ों लोगों को अपने जन्म और अस्तित्व तथा नागरिक अधिकारों के लिए दस्तावेजों के होते हुए भी प्रमाण देने पड़ें। तब स्वाभाविक रूप से नागरिकों में असुरक्षा और असंतोष बढ़ना तय है। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा एक बड़े आंदोलन और राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। कानून व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। जिस तरह से देश में स्थितियां बदल रही हैं, ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरगामी परिणाम देने वाला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टि से चुनाव आयोग की शक्तियों को मजबूत करता है।

सैमसंग कंपनी ने एआई चिप्स की भारी डिमांड से कमाया रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा

78,000 कर्मचारियों को औसतन 50.9 करोड़ का ऐतिहासिक बोनस देगी कंपनी

नई दिल्ली।

दुनिया भर में एआई से सबसे ज्यादा फायदा दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप डिवीजन के कर्मचारियों को हुआ है। ग्लोबल मार्केट में एआई चिप्स की भारी डिमांड और कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे के चलते सैमसंग ने करीब 78,000 कर्मचारियों को औसतन 50.9 करोड़ 3.7 लाख डॉलर का ऐतिहासिक बोनस देने जा रही है। इस बंपर मेगा-बोनस स्कीम और नए वेतन समझौते पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इससे पहले सैमसंग के मुकाबले उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी एसके हाइनेवे स अपने कर्मचारियों को तीन गुना ज्यादा बोनस दे रही थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते को मंजूर करने के लिए करीब 70,000 यूनियन सदस्यों के बीच बीते शुक्रवार से इलेक्ट्रॉनिक मतदान शुरू हुआ है। वोटिंग बुधवार को खते म होगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 90फीसदी से ज्यादा सदस्य पहले ही वोट डाल चुके हैं और बहुमत के साथ इसके आज ही मंजूर होने की पूरी संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैमसंग का यह कदम उसके टैलेंटेड इंजीनियरों को विदेश जाने से रोकने के लिए जरूरी था। इस समय एलन मस्क की कंपनी टेस्ला समेत कई अमेरिकी दिग्गज एआई चिप्स में भारी निवेश कर रहे हैं।

सैमसंग और उसकी सबसे बड़ी लेबर यूनियन के बीच समझौता 10 सालों के लिए लागू रहेगा। इस बोनस समझौते को कंपनी के परफॉर्मेंस टारगेट से जोड़ा है। बोनस दो हिस्सों में दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलने वाला सालाना बोनस चिप डिवीजन के कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 10.5 फीसदी होगा, जिसे कंपनी के शेयर्स के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को 1.5 फीसीदी अतिरिक्त बोनस नगद मिलेगा। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर कंपनी का वार्षिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तय लक्ष्य 331 ट्रिलियन वॉन तक पहुंच जाता है, तो हर एक पात्र कर्मचारी को इस साल औसतन 3.7 लाख डॉलर का फायदा होगा।

एचडीएफसी ने खेला ज्यादा ब्याज देने का खेल, गवर्नेंस और ट्रांसपरेंसी पर उठे सवाल

मार्च में बैंक के चेयरमैन ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली।

देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी पर आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआरडीसी) को तय नियमों से ज्यादा ब्याज देने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए को मार्केटिंग खर्च के रूप में बैंक ने दिखाया था। बैंक की इंटरनल चेकिंग में इस पूरी व्यवस्था को नियमों के खिलाफ बताया है। मामला सामने आने के बाद बैंक की गवर्नेंस और ट्रांसपरेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि यह फैसला इस विवाद से जुड़ा हुआ था। कई रिपोर्ट्स से यह भी सामने आया है कि बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के साथ अधिकार और फैसलों को लेकर चल रहे मतभेदों के कारण अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच रणनीति, गवर्नेंस और सीईओ की दोबारा नियुक्ति को लेकर तनाव था। अब जांच रिपोर्ट में बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवल्पमेंट कारपोरेशन ने बैंक में बड़ी राशि जमा करने को लेकर बातचीत शुरू की थी। एमएसआरडीसी ने अपनी जमा राशि पर 6.01 फीसदी ब्याज की मांग की थी, जबकि उस समय बैंक सामान्य बचत खातों पर करीब 3.5 फीसदी ब्याज दे रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि एमएसआरडीसी ने बैंक में करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा करने की बात कही थी। इस बड़े डिपॉजिट के लिए बैंक ने विशेष व्यवस्था बनाई। हालांकि, आरबीआई के नियमों के कारण बैंक सीधे तौर पर इतनी ऊंची ब्याज दर नहीं दे सकता था। इसके बाद ब्याज के अंतर को दूसरे तरीके से देने की योजना बनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक किसी एक ग्राहक को स्पेशल बेनिफिट देने के लिए अलग ब्याज व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में बैंक की एंटी-ब्राइबरी और गवर्नेंस पॉलिसी का भी उल्लंघन हुआ है। इंटरनल विजिलेंस रिपोर्ट में बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन, सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह पूरी व्यवस्था सामान्य बैंकिंग प्रोसेस और निगरानी से बाहर थी।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 141, निफ्टी 7 अंक गिरा

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से भी निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाये रखी। इससे भी भारतीय बाजार पर दबाव आया है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सेंसेक्स 141.90 अंकों की गिरावट के साथ ही 75,867.80 के स्तर पर बंद हुआ।

वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 6.55 अंक फिसलकर 23,907.15 अंक पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट वित्तीय और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में रही। निफ्टी के जिन शेयरों में गिरावट रही उनमें ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर रहे जबकि उर्जा और धातु क्षेत्र के शेयरों में तेजी रही। वहीं सेंसेक्स के शेयरों में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन,और एनटीपीसी के शेयरों में तेजी रही। टाटा स्टील, इंडिगो, मारुति सुजुकी, टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयर भी उछले हैं। बाजार जानकारों के अनुसार अमेरिका के ईरान पर ताजा हमलों के बाद दोने में तनाव बढ़ा है जससे भी निवेशकों में घबराहट है और वह सतर्कता बरत रहे हैं। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बना हुआ है।

आज निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और वित्तीय सर्विसेज इंडेक्स क्षेत्र में शेयर गिरे जबकि .मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्र में तेज रही। छोटे और मझोले शेयरों में खरीदारी देखी! इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुला।

सुबह सेंसेक्स 136.38 अंक फिसलकर 75,873.32 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 29.95 अंक टूटकर 23,887.15 पर था।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 8 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.63 पर बंद हुआ इससे पहले आज सुबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.75 पर खुला। वहीं महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों में कुछ गिरावट से निवेशकों को कुछ राहत मिली है। कारोबारियों के अनुसार आरबीआई की डॉलर बिक्री से रुपये को ऊपरी स्तरों पर समर्थन मिला। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से भी बाजार में गिरावट का माहौल है जिससे भी रुपया दबाव में रहा।

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के वायदा भाव में तेजी आई है। आज सुबह कमजोर शुरुआत के बाद सोने में तेजी आने लगी। वहीं चांदी के भाव बढ़त पर ही खुले। घरेलू बाजार में आज सोने की वायदा कीमतें 1,57,850 रुपये, जबकि चांदी की 2,72,400 रुपये पर बनी हुई थीं। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इन दोनो ही कीमती धातुओं में तेजी रही। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज कमजोर रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क जून अनुबंध आज 75 रुपये फिसलकर 1,57,541 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 1,57,616 रुपये था। सोने के वायदा भाव इस साल 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे थे। दूसरी ओर चांदी के वायदा भाव की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क जुलाई अनुबंध आज 1,975 रुपये बढ़कर 2,72,603 रुपये पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 2,70,628 रुपये था। चांदी के भाव 3 लाख रुपये पार कर चुके हैं। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस दोनो के ही वायदा भाव में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना आज 4,507.40 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 4,502.30 डॉलर प्रति औंस था। सोने का भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर भी पहुंचा। कॉमैक्स पर चांदी के वायदा भाव 77.33 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला क्लोजिंग प्राइस 76.60 डॉलर था।

8वें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा

आईआरटीएसए ने सरकार के सामने रखा 5-टियर फिटमेंट फॉर्मूला

नई दिल्ली।

8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता है। खासतौर पर रेलवे कर्मचारियों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि नए वेतन आयोग में उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसी बीच रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के संगठन ने सरकार के सामने एक नया और अलग प्रस्ताव रखा है, जिससे रेलवे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने 8वें वेतन आयोग के सामने रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग 5-टियर फिटमेंट फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। अब तक सभी वेतन आयोगों में कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय थी। हालांकि, संगठन का कहना है कि रेलवे तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, कार्य का दबाव और जोखिम अन्य कर्मचारियों से अलग और चुनौतीपूर्ण है। इसलिए उनके लिए अलग वेतन व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 6 से 8 तक के लिए 3.50, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 तक के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 तक के कर्मचारियों के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में

रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 45 हजार है और वह लेवल 6 से 8 के दायरे में आता है, तो 3.50 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 1.57 लाख रुपए हो जाएगी।

संगठन ने संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना यानी एमएसीपी में भी बदलाव की मांग की गई है। प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को 30 साल की सेवा अवधि में पांच बार वित्तीय उन्नयन देने की सिफारिश की गई है। अब सभी की नजर सरकार और 8वें वेतन आयोग के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इससे लाखों रेलवे कर्मचारियों की आय और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव हो सकता है।

ओएनजीसी का मार्च तिमाही में मुनाफा घटा, कमाई बढ़ी

कंपनी ने किया निवेशकों को 1 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान

नई दिल्ली।

सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी का मार्च तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे। कंपनी का मुनाफा घटा है, लेकिन कमाई बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 20.6 फीसदी गिरकर 6,650 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी को 8,371 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हालांकि, इस दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 35,928 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो एक साल पहले 31,547 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो कंपनी का कुल शुद्ध लाभ 32,894 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7.6 फीसदी कम है। पिछले साल कंपनी ने 35,610 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। ओएनजीसी को खोजी कुओं पर बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। कंपनी ने मार्च तिमाही में 4,876 करोड़ रुपए का खर्च लिखकर हटाया, क्योंकि जिन जगहों पर ड्रिलिंग की गई वहां तेल या गैस का व्यावसायिक भंडार नहीं मिला। पिछले साल इसी तिमाही में यह नुकसान 4,173 करोड़ रुपए था। वहीं पूरे साल में ऐसे खर्च का आंकड़ा बढ़कर 8,235 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर दाहेज में 5 एमएमटीपीए क्षमता

वाला लिक्विड पोर्ट बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा ओएनजीसी ने ओएनजीसी नाइल गंगा के लिए 325 मिलियन डॉलर की गारंटी को भी मंजूरी दी है। ओएनजीसी ने अपने निवेशकों के लिए 1 रुपए प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि यह 5 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 20 फीसदी की दर से दिया जाएगा। हालांकि इसे एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी मिलना बाकी है।

बता दें मंगलवार को ओएनजीसी का शेयर 0.89 फीसदी की बढ़त के साथ 287.50 रुपए पर बंद हुआ था। दिन के कारोबार में शेयर ने 289.65 रुपए का ऊपरी स्तर और 284.50 रुपए का निचला स्तर छुआ।

टाटा संस की मैराथन बैठक में नोएल टाटा ने नए जमाने के कारोबार के किए सवाल

बैठक में कंपनी को सूचीबद्ध कराने और न ही चंद्रशेखरन के कार्यकाल पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। बॉम्बे हाउस में मैराथन बोर्ड बैठक भले ही टाटा समूह की कंपनियों के राजस्व, मुनाफा, प्रति शेयर आय (ईपीएस) और अन्य तमाम आंकड़ों की प्रस्तुति वाले किसी रोड शो जैसी लगी हो लेकिन इस समीक्षा सत्र को टाटा ट्रस्ट्स के साथ जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करने वाले इस समूह की मूल कंपनी में टाटा ट्रस्ट्स सबसे बड़ा शेयरधारक है। बता दें लोगों को इस बैठक का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इसमें न तो होल्डिंग कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने पर और न ही चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर कोई चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों मुद्दों पर 12 जून को होने वाली अगली बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है। एक अनोखे घटनाक्रम के तहत टाटा संस की एक विशेष बोर्ड बैठक 26 मई को बुलाई गई थी जहां घाटे में चल रही समूह की कुछ कंपनियों के वित्तीय नतीजों, अनुमानों और रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें कई मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अपनी पावर पॉइंट प्रस्तुतियों के साथ शामिल हुए। वास्तव में यह बैठक 24 फरवरी को हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और नामित निदेशक नोएल टाटा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब थी।

क्वाड देश महत्त्वपूर्ण खनिजों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के लिए जुटाएंगे 20 अरब डॉलर

नई दिल्ली।

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने 'क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क' पेश किया। इस ढांचे के तहत चारों देशों ने खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण समेत खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से 20 अरब डॉलर तक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की इच्छा जताई है। नई दिल्ली में घोषित इस ढांचे का मकसद रणनीतिक संसाधनों पर बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों एवं औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले अहम खनिजों के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने से जुड़ी पहल को बढ़ावा देना है।

इस पहल के तहत 'क्वाड' भागीदार 'क्वाड नेक्सस' वाली परियोजनाओं की पहचान करने की योजना की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जिनमें सदस्य देशों में स्थित परियोजनाएं, इन देशों में मुख्यालय वाली कंपनियों द्वारा संचालित परियोजनाएं या क्वाड बाजारों को आपूर्ति करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।

समूह ने निर्यात ऋण एजेंसियों, विकास वित्त संस्थानों, गारंटी, ऋण, इक्विटी भागीदारी, बीमा, सब्सिडी और निजी पूंजी के जरिये रणनीतिक तौर पर अहम खनिज परियोजनाओं का समर्थन करने की भी पेशकश की। मंगलवार को 'क्वाड' देशों ने ई-कचरा और स्क्रैप सामग्री से महत्त्वपूर्ण खनिज दोबारा हासिल कर पुनर्चक्रण में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा। इसमें पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों, संग्रह नेटवर्क में निवेश और कचरा और स्क्रैप के लिए निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है।

इसके अलावा, भारत और अमेरिका ने 'महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने' पर एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्ताक्षर किए।

बाजार में बढ़ा नकली और कम शुद्धता वाली चांदी का कारोबार, नहीं पहचान पा रहे ग्राहक

चांदी पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य, कई ज्वेलर्स नहीं कर रहे इसका पालन

नई दिल्ली।

देश में चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों और निवेशकों की मजबूत मांग के बीच नकली और कम शुद्धता वाली चांदी का कारोबार तेजी से बढ़ा है। बाजार में बिक रही कई सिल्वर बार, सिक्के, आभूषण और पूजा सामग्री तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। इससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान का खतरा है, वहीं चांदी बाजार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के महीनों में निवेशकों का रुझान सोने के साथ-साथ चांदी की ओर भी बढ़ा है। सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में लोग बड़ी मात्रा में सिल्वर बार, सिक्के और चांदी के बर्तन खरीद रहे हैं।

इसी बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी और अवैध निर्माता बाजार में कम गुणवत्ता वाली चांदी बेच रहे हैं। उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि बाजार में बड़ी मात्रा में ऐसी चांदी मौजूद है, जो 999 शुद्धता के मानक को पूरा नहीं करती है। विशेष चिंता की बात यह है कि कई उत्पादों में निकेल, कैडमियम और लेड जैसे हानिकारक तत्व भी पाए जा रहे हैं। ये धातुएं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक स्क्रैप सिल्वर से बने आभूषणों और अन्य वस्तुओं में इस तरह की मिलावट ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे ग्राहकों की सुरक्षा और निवेश दोनों प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने सितंबर 2025 से चांदी की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है, लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में ज्वेलर्स इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए असली और नकली चांदी की पहचान करना कठिन है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह सोने के लिए सख्त हॉलमार्किंग और लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू है, उसी प्रकार चांदी के क्षेत्र में भी मजबूत निगरानी तंत्र जरूरी है। जानकारी के मुताबिक भारत में हर साल करीब 7,000 टन चांदी की खपत होती है, जबकि इसके लिए केवल 286 अस्सेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर उपलब्ध हैं। इसके विपरीत सोने की खपत कम होने के बावजूद उसके लिए 1,500 से ज्यादा सेंटर मौजूद हैं। यही असंतुलन चांदी बाजार की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। जयपुर, आगरा, राजकोट, कोल्हापुर, सलेम और कटक जैसे शहर चांदी के आभूषण और धार्मिक वस्तुओं के बड़े उत्पादन केंद्र हैं।

ब्रिटानिया 'गुड डे' अब होगा महंगा! कंपनी फैमिली पैक्स के बढ़ा रही दाम

5 और 10 रुपए वाले पैक्स की एमआरपी में बदलाव नहीं, कम होगा वजन

नई दिल्ली।

अगर आप भी सुबह या शाम की चाय के साथ ब्रिटानिया का 'गुड डे' बिस्किट खाते हैं तो अब इस शौक के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाना होगा। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 'गुड डे' बिस्किट के फैमिली पैक्स के दाम बढ़ा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसके प्रमुख वैरिएंट्स की कीमतों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटानिया 5 और 10 रुपए वाले पैक्स की एमआरपी में कोई बदलाव तो नहीं होगा लेकिन इसका वजन कंपनी कम कर सकती है यानी आपको पैसे तो उतने ही देने होंगे, लेकिन पैकेट में बिस्किट कम मिलेंगे। कंपनी ने अपनी अर्निंग्स कॉल में भी साफ कहा है कि 10 रुपए से महंगे पैक्स पर दाम बढ़ाए जाएंगे और छोटे पैक्स में वजन कम किया जाएगा। कंपनी कच्चे माल की कीमतों और पैकेजिंग मैटेरियल की बढ़ती कॉस्ट से परेशान है। इसी वजह से कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। बता दें ब्रिटानिया की कुल कमाई में बिस्किट कारोबार की हिस्सेदारी 70-75 फीसदी है, और अकेले 'गुड डे' ब्रांड से कंपनी को करीब 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। कीमतें बढ़ाने का यह फैसला कंपनी के चौथी तिमाही के मिले-जुले नतीजों के बाद आया है। मार्च तिमाही में ब्रिटानिया का कुल रेवेन्यू 6.5फीसदी बढ़कर 4,719 करोड़ रुपए रहा। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ भी उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए 21.1फीसदी की बढ़त के साथ 678 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि, विज्ञापनों और अन्य खर्चों में 17.5फीसदी की भारी बढ़ोतरी होने के कारण कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती महीनों में कंपनी का बिजनेस करीब 9फीसदी की रफ्तार से बढ़ा था, लेकिन मार्च आते-आते इस पर ब्रेक लग गया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई। इसके कारण समुद्री मालभाड़ा और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसने कंपनी की लागत को बढ़ा दिया। यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने ब्रिटानिया के शेयर पर अपनी 'बाय' रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 7,170 रुपए से घटाकर 6,360 रुपए कर दिया है।

जेके सीमेंट कंपनी बढ़ा रही क्षमता, बढ़ती लागत से निपटने बढ़ाए दाम

कंपनी की कुल ग्रे सीमेंट क्षमता बढ़कर 32.3 एमटीपीए हो गई

नई दिल्ली।

सीमेंट कंपनी जेके सीमेंट के मार्च तिमाही नतीजों के बाद बाजार में कंपनी को लेकर चर्चा बढ़ गई है। कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती लागत से निपटने सीमेंट के दाम भी बढ़ा रही है। आने वाले समय में कंपनी का फोकस ज्यादा बिक्री पर है, नई यूनिट्स और लागत कंट्रोल पर रहने वाला है। कंपनी ने 2027 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2028 तक कुल क्षमता को करीब 40 एमटीपीए तक पहुंचाने की योजना है। बिहार में 30 लाख टन क्षमता वाला नया यूनिट भी शुरू हो चुका है, जिससे कंपनी की कुल ग्रे सीमेंट क्षमता बढ़कर 32.3 एमटीपीए हो गई है।

हालांकि, ईंधन, डीजल और पैकेजिंग लागत बढ़ने से कंपनी पर दबाव बना हुआ है। कंपनी का कहना है कि पहली तिमाही में ईंधन लागत करीब 150-200 रुपए प्रति टन तक बढ़ सकती है। डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ सकता है। इसके असर को कम करने के लिए कंपनी ने ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने ग्रे सीमेंट में करीब 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की है।मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर बाय रेटिंग रखते हुए 6,250 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का चौथी तिमाही का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा। हालांकि ईबीआईटीडीए और मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। कंपनी का ईबीआईटीडीए करीब 11 फीसदी घटकर 680 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रति टन ईबीआईटीडीए करीब 1,008 रुपए पर आया। ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाले समय में ईंधन लागत बढ़ने का असर कंपनी के मार्जिन पर दिखेगा। फिर भी कंपनी की बिक्री बढ़ाने की योजना और लगातार विस्तार को देखते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखी है।नुवामा ने जेके सीमेंट पर 7,034 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की ग्रे सीमेंट बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च तिमाही में बिक्री 14 फीसदी बढ़ी, जबकि पूरे साल में यह ग्रोथ 17 फीसदी रही।

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसलाः राशन व्यवस्था होगी हाईटेक

80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की तैयारी

'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी, डीलरों का बढ़ेगा कमीशन और राज्यों को मिलेगी आर्थिक सहायता

नई दिल्ली,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बधुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार राशन वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनसे राज्यों, राशन डीलरों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

राज्यों को आर्थिक सहायता

कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला राज्यों को आर्थिक सहायता देने से जुड़ा है। मंत्री ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बड़े गोदामों से अनाज को जिलों, ब्लॉकों और अंततः राशन दुकानों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब केंद्र सरकार इस परिवहन और वितरण व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी, जिससे राशन आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुचारु हो सकेगी।

राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन

कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ाने का है। लंबे समय से राशन दुकानदार अपने कमीशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।

सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे देशभर के लाखों राशन डीलरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

लाभार्थियों का पंजीकरण

कैबिनेट का तीसरा और सबसे अहम फैसला जो राशन व्यवस्था

को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का है। सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीकों की मदद से लाभार्थियों का पंजीकरण करेगी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सही व्यक्ति तक राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल और तकनीक आधारित व्यवस्था से पूरे पीडीएस नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

भीषण गर्मी पर हुई चर्चा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान देश में जारी भीषण लू की स्थिति पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 'पूरे राष्ट्र की भावना' के साथ काम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य, जल संसाधन और अन्य विभागों द्वारा नागरिकों को राहत और सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर विशेष चर्चा की गई।

टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस को सांसदों और विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार का असंतोष खुलकर सामने आ गया। काकोली घोष ने हाल ही में टीएमसी के बारासात जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अब पार्टी संगठन में अन्य सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। घोष ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा है। काकोली घोष ने सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी संगठन में सभी पद छोड़ रही हूं। हालांकि, काकोली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। काकोली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई हैं।

कसौली जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर

वन विभाग की टीमों के साथ फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी

नई दिल्ली।

उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी में अब जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में जंगलों में आग लग गई। यह आग देखते ही देखते कसौली स्थित एयरफोर्स स्टेशन के करीब तक पहुंच गई है तो अब एयरफोर्स भी एक्टिव मोड में आ गई है। एयरफोर्स ने जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए दो हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। वन विभाग की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के काम में जुटी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन आग और फैलती जा रही है। कसौली के जंगलों में लगी इस आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात बिगड़ते, आग की लपटें एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंचते देख एयरफोर्स ने दुर्गम क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए एमआई-17 और चिनूक हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। एयरफोर्स के ये हेलिकॉप्टर चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कसौली के जंगलों की आग अभी काबू भी नहीं हो सकी है कि अब शिमला के पास राजहाना गांव के पास भी जंगल में आग लग गई है।

अमित शाह का दो दिवसीय गुजरात दौराः हरामी नाला में सुरक्षा पर पैनी नजर

नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे है। जिसमें वे भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अत्यंत संवेदनशील हरामी नाला चौकी का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने वाले है। 28-29 मई को निर्धारित यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हरामी नाला विवादित सर क्रीक क्षेत्र के करीब कच्छ के रण में स्थित एक संवेदनशील खाड़ी क्षेत्र है।

भुज के पास कच्छ जिले में स्थित क्षेत्र अपनी उथली, दलदली और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह खाड़ी प्रणाली निगरानी में चुनौतीपूर्ण है, जिससे यह अवैध घुसपैठ, तस्करी, संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही और संभावित आतंकी मार्गों के लिए अतिसंवेदनशील बनी हुई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इस क्षेत्र से कई बार पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया है, जो इसकी संवेदनशीलता को दिखाता है।

अपने दौरे के पहले दिन, श्री शाह गांधीनगर और अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले है। इसमें नवनिर्मित जेडवा गांव तालाब, एक नए वाचनालय, और टोयोटा किर्लोस्कर लिमिटेड तथा गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। वे ग्राम पंचायत कार्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों और अतिरिक्त पुस्तकालयों का उद्घाटन भी करने वाले हैं, साथ ही विभिन्न गांवों में तालाब

सौंदर्यीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले है। अहमदाबाद में, गृह मंत्री केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय, माता उमिया धाम छात्रावास भवन और भारत माता सक्रायर का उद्घाटन करने वाले है। वे ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की तैयारियों की भी समीक्षा करने वाले है।

9 मई को, शाह विशेष रूप से भुज स्थित सीमा चौकी हरामी नाला पर जाएंगे। वे जी-7 प्रहरी सम्मेलन का उद्घाटन और चौकी का विस्तृत निरीक्षण करने वाले है। इस दौरान, वे नियंत्रण कक्ष में पीटीजेड निगरानी कैमरों की फुटेज की समीक्षा करने और नाव से पूरे हरामी नाला क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेने वाले है।

योगेंद्र यादव का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मंच जैसा काम किया

नई दिल्ली।

चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यादव ने आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत ने संवेदनशील मामले में संवैधानिक अदालत के बजाय एक उपभोक्ता मंच की तरह काम किया है। उन्होंने दावा किया कि अंतिम फैसला बहुत पहले ही तय हो चुका था। यादव ने कहा कि वे अंतिम फैसला सुनने के लिए अदालत नहीं गए, क्योंकि उनके विचार में सिर्फ लिखित दस्तावेज और बारीकियाँ ही बाकी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दिनों की सुनवाई के बावजूद, पीठ ने एसआईआर की संवैधानिकता की जांच करने के बजाय शिकायत निवारण और मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित किया। यादव के अनुसार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग

(ईसीआई) को एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों में कथित खामियों को दूर किए बिना ही बिहार चुनाव कराने की अनुमति दे दी, तभी मामला प्रभावी रूप से तय हो गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया संचालित करने की शक्ति को बरकरार रखा है, यह कहकर कि यह लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को नई जान देती है। यह फैसला चुनाव आयोग पर लगे उन आरोपों के बीच आया है, जिसमें आलोचकों ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के पीछे राजनीतिक मकसद होने का दावा किया था।

भारत में इबोला का कोई खतरा नहीं, युगांडा से आई महिला की रिपोर्ट नेगेटिव

नई दिल्ली।

भारत सरकार ने बुधवार को साफ कर दिया कि देश में इबोला वायरस से जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है। यह घोषणा युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला जैसे हल्के लक्षण दिखने के बाद की गई थी, हालांकि महिला की टेस्ट रिपोर्ट नकारात्मक आई है। यह महिला 23 मई बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, इसके बाद एहतियातन महिला को सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। शुरुआती तौर पर उसमें हल्का शारीरिक दर्द था, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। अधिकारियों ने घबराने की आवश्यकता से इंकार करते हुए एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। महिला के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि अफ्रीकी देश युगांडा में इबोला के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इबोला वायरस डिसीज (ईवीडी) पहली बार 1976 में अफ्रीका में सामने आई थी और यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त, उल्टी और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलती है। इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित 25 से 90 प्रतिशत मरीजों की मौत हो सकती है। वर्तमान में, कांगो के पूर्वी इटुरी प्रांत में इबोला से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 246 संदिग्ध मामले सामने आए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, हालांकि अभी महामारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन मिला है, जबकि कांगो में पहले जायरे स्ट्रेन के मामले अधिक थे, जिससे मौजूदा उपचार और टीकों की प्रभावशीलता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 गिरफ्तार

एजेंसी अब तक देशभर में 49 स्थानों पर चला चुकी है तलाशी अभियान

नई दिल्ली।

सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों की 13 हो गई है। सीबीआई के मुताबिक लातूर निवासी डॉक्टर मनोज शिरुरे को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी वी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की पहचान तेजस हर्षदकुमार शाह के रूप में हुई है। वह पुणे स्थित डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी में भौतिकी के फैकल्टी सदस्य हैं।

सीबीआई के मुताबिक उन्हें नीट-यूजी 2026 परीक्षा का लीक हुआ भौतिकी का प्रश्नपत्र पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिला था। एजेंसी अब तक देशभर में 49 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है। सीबीआई ने यह मामला 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में नीट-यूजी 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की बात कही थी।

सीबीआई के मुताबिक जांच में पता चला है कि परीक्षा से पहले रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नपत्र प्रसारित किए गए थे।

एजेंसी अब प्रश्नपत्र लीक के असली स्रोत और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वह इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिमाचलः पहाड़ दरकने से जाहलमा पुल टूटा, कार नदी में गिरी

शिमला ।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बिन बरसात ही कुदरत का भारी कहर देखने को मिला है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण तांदी-संसारी मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण आखिरकार ऐतिहासिक जाहलमा पुल टूट कर नदी में समा गया है। बीते तीन दिनों से इस पुल के एक छोर पर पहाड़ी से लगातार भारी चट्टानें गिर रही थीं, जिसके चलते अब पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह धराशाई हो गया है। इस आपदा के कारण उदयपुर का लाहौल के मुख्य केंद्र केलांग और मनाली से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जाहलमा पुल के टूटने से घाटी के लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। अब यदि स्थानीय निवासियों या पर्यटकों को मनाली या शेष हिमाचल के अन्य हिस्सों में जाना है, तो उन्हें पांगी घाटी होते हुए खतरनाक साच पास को पार कर चंबा के रास्ते सफर करना होगा। इस वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने में लोगों को करीब दो दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। इसी बीच लाहौल की मूलिंग घाटी से भी एक और दर्दनाक हादसे की खबर आई है, जहां बीती रात करीब 10 बजे अचानक पहाड़ी दरक गई। इस लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक चलती कार अनियंत्रित होकर सीधे उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में केवल चालक ही सवार था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और मुस्तैद पुलिस बल ने तुरंत संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कार सवार को सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर केलांग अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मूलिंग में आए दिन

लैंडस्लाइड होता रहता है, जिससे हर वक्त लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहता है। इससे पहले मंगलवार को भी मूलिंग में भारी चट्टानें गिरने से लेह-मनाली नेशनल हाईवे घंटों बंद रहा था।

तीन दिनों से रुक-रुककर दरक रहे पहाड़

प्रशासन के अनुसार, लाहौल घाटी के उदयपुर स्थित जाहलमा में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें गिर रही थीं, जिसके खौफनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने मंगलवार को इस मार्ग पर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने का फरमान सुनाया था, लेकिन अब पूरी पहाड़ी के दरकने से यह मार्ग पूरी तरह ठप्प हो गया है। पहाड़ी से विशालकाय चट्टानें गिरने के कारण सड़क पर भी गहरी और बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मार्ग को दोबारा सुचारू करने में कम से कम एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है।

हरियाणा में युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जिला स्तर पर लगेंगे रोजगार मेले, कौशल प्रशिक्षण पर रहेगा जोर

अस्पताल परियोजनाओं की प्रगति की भी मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

चंडीगढ़ ।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग मिलकर युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देंगे, ताकि उन्हें उद्योगों में बेहतर अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा भी की। फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल में निर्माणाधीन मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय पर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

पूर्व सीएम विजयन के घर रेड करने पहुंचे ईडी अफसरों पर पत्थरबाजी

विजयन के साथ ही उनकी बेटी के आवास पर भी छापेमारी

तिरुवनंतपुरम ।

तिरुवनंतपुरम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के बाहर निकलने के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। कन्नूर में पूर्व सीएम विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद जांच अधिकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए ईडी अधिकारियों से सवाल पूछने लगे, जिससे गेट पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। काफी देर तक धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, इसके बाद सुरक्षाकर्मियों की मदद से अधिकारियों को बाहर निकाला गया।बात दें कि ईडी की कार्रवाई ने केरल की राजनीति में सियासी घमासान तेज किया है। सीपीआई(एम) के महासचिव एम.ए. बेबी ने मोदी सरकार और ईडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सीपीआई(एम) के महासचिव बेबी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत दी। उन्होंने दावा किया कि ईडी अब एक स्वतंत्र एजेंसी के बजाय भाजपा सरकार की राजनीतिक मशीनरी बन गई है, जिसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को केरल में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और उनकी बेटी वीणा के आवास भी शामिल थे। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है, जिसमें विजयन की बेटी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस का नाम सामने आया है। यह मामला कोच्चि स्थित कोच्चि मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित अवैध भुगतानों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

ईडी की छापेमारी का मुख्य आधार अप्रैल 2025 में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा दायर चार्जशीट है। एसएफआईओ ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस पर आरोप लगाया है कि उसने 2018-19 से तीन वर्षों तक सीएमआरएल से बिना कोई सेवा दिए अवैध भुगतान प्राप्त हुए थे। 2017 में एक्सालॉजिक और सीएमआरएल के बीच सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सेवाओं के लिए अनुबंध हुआ था, लेकिन जांच में पाया गया कि निर्धारित सेवाएं प्रदान नहीं की गईं। इस कथित

वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा सबसे पहले 2019 में आयकर विभाग की सीएमआरएल परिसरों पर हुई छापेमारी के दौरान हुआ था, जिसकी रिपोर्ट में संदिग्ध भुगतानों का उल्लेख था। जनवरी 2024 में केंद्र ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस, सीएमआरएल और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसएफआईओ को आदेश दिए थे। सीएमआरएल में सरकारी संस्था केएसआईडीसी की 13.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसएफआईओ की जांच और आयकर विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाकर ईडी ने मार्च 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके तहत ये छापेमारी की गई है।

सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी से दबोचा गया शातिर लुटेरा

40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में दर्ज है आरोपी का नाम

लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद

नई दिल्ली ।

पश्चिमी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी राहुल (28) को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तम नगर इलाके का निवासी है और उसके खिलाफ लूट, झपटमारी समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए 13 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 23 मई की रात ख्याला थाना क्षेत्र में एक युवक से 15 हजार रुपये लूटे गए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की पहचान की। जांच के दौरान पता चला कि राहुल दिल्ली पुलिस के छह मामलों में घोषित अपराधी भी रह चुका है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे जांच जारी है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717